डा. हर्ष वर्धन: साथ ही Wildlife के भी डिपार्टमेंट्स हैं। We have provided adequate preventive and protective measures to all. …*(Interruptions)*…

MR. CHAIRMAN: Thank you, Mr. Minister. Now, K.J. Alphons. You are connected with Kerala.

SHRI K.J. ALPHONS: Sir, the State of Kerala has one of the most vibrant health systems. But, how come, every few months, there is an outbreak of some calamity or the other in the health sector? Has the Central Government made any study on this? If yes, what is the long-term solution to this?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I think, the best way to handle all this is by having the best possible surveillance system for various diseases. Of course, there is already a robust surveillance system in the whole country. I think, there is a well-established system in Kerala too. But, there is always scope to further better the facilities that we are already providing to our people. You cannot eradicate the diseases that are endemic to a particular place. But you can certainly handle them in a far better fashion by an early diagnosis.

प्रो. मनोज कुमार झा: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा एक प्रश्न है और प्रश्न के साथ यह निवेदन है कि Encephalitis, जिसको हम कहते थे कि गोरखपुर-मुजफ्फरपुर कॉरिडोर में उसकी बहुत proneness होती है, वह असम तक भी spread हुआ है। 2014 में भी आपने कुछ intervention करने की कोशिश की थी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अनुसंधान की दिशा में या preventive medical care के लिए कुछ proactive steps लिए जा रहे हैं, ताकि अगले वर्ष इसकी पुनरावृत्ति न हो?

डा. हर्ष वर्धन: महोदय, Encephalitis की दृष्टि से दो aspects हैं। यह एक है कि Japanese Encephalitis वायरस के कारण होता है। उसके लिए माननीय सदस्य को और सदन को मैं बताना चाहूंगा कि 2014 के बाद ही Japanese Encephalitis का जो vaccination है, वह भारत में, खास कर जो endemic districts हैं, उनमें उसको Universal Immunization Programme के माध्यम से सब जगह दिया जाता है। दूसरा जो इसी के साथ मिलता-जुलता है, वह Acute Encephalitis Syndrome है, जिसमें बीमारी Encephalitis जैसी होती है, लेकिन उसके जो कारण हैं, उसके बारे में विभिन्न व्यूज़ हैं। वे टॉक्सिक भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं। उसके संदर्भ में, भारत में पर्याप्त रिसर्च हो रही है। जितनी भी संबंधित एसेंसीज़ हैं.. लेकिन अभी हम लोगों ने सजेस्ट किया है कि मुजफ्फरपुर जैसी जो जगहें हैं, जहां पर वह डिजीज़ बहुत ज्यादा endemic हर साल आती है, वहां पर जो state-of-the-art inter-disciplinary research centers हैं, इनको consistently throughout the year काम करना चाहिए, rather than through big institutions all over the country.

बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के कण पाया जाना

*108. **डा. किरोड़ी लाल मीणा**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर में उपयोग किए जा रहे बोतल बंद पानी में प्लास्टिक के बारीक कण घुल जाते हैं जो मानव शरीर के लिए घातक साबित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. हर्ष वर्धन): (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) बोतलबंद पानी में प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में ओआरबी मीडिया के माध्यम से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसने फ्रेडोनिया में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के भूविज्ञान और पर्यावरण विज्ञान विभाग में पैकेज्ड पेयजल के विभिन्न ब्रांडों पर एक शोध किया और सूक्ष्म प्लास्टिक की मौजूदगी की सूचना दी।

उपरोक्त रिपोर्ट के संबंध में, इस मामले को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साइंटिफिक पैनल ऑन वॉटर (फ्लेवर्ड वाट सहित) एंड ब्रेव्रिजिज (अल्कोहलिक और गैर-अल्कोहलिक) के समक्ष रखा गया और भारतीय पैकेजिंग संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, सेंट्रल साल्ट, मरीन एंड केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की टिप्पणियां मांगी गई और इसे वैज्ञानिक पैनल के समक्ष रखा गया था। वैज्ञानिक पैनल ने विस्तृत जांच के बाद कहा कि चूंकि प्लास्टिक की बोतलों पर खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के वर्तमान विनियमों में खाद्य पदार्थों के संपर्क में प्लास्टिक की सुरक्षित समग्र माइग्रेशन सीमा 60 एमजी/किग्रा के रूप में निर्दिष्ट है, इसलिए इसमें पानी में किसी भी सूक्ष्म प्लास्टिक का माइग्रेशन शामिल होगा। माइक्रो प्लास्टिक कणों का समग्र वजन लगभग 0.01 एमजी/किग्रा होना सुरक्षित सीमा के भीतर रहेगा।

खाद्य पदार्थ में समग्र माइग्रेशन की जांच करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के उप-विनियमन 4 के खंड (4) के उप-खंड (ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैं;

'किसी भी दृश्य रंग माइग्रेशन के बिना आईएस 9845 के अनुसार जांच किए जाने पर, प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्रियों को 60 एमजी/किग्रा. या 10 एमजी/डीएम2 की निर्धारित समग्र माइग्रेशन सीमा का पालन (पास) कराना होगा'।

Plastic particles in bottled water

†*108. DR. KIRODI LAL MEENA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the fact that fine plastic particles get dissolved with the water contained in bottles being consumed across the country, prove to be fatal for human body;

(b) if so, whether steps have been taken by Government to provide clean drinking water to the people, if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) to (c) A report on plastic pollution in bottled water was received through Orb media which conducted a research at State University of New York at Fredonia, Department of Geology and Environmental Sciences on various brands of packaged drinking water and reported the presence of micro plastics.

In regard to above report, the matter was placed before the Scientific Panel on Water (including Flavoured Water) and Beverages (Alcoholic and Non-Alcoholic) of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) and comments from Institutes like Indian Institute of Packaging and Indian Institute of Toxicological Research, Central Salt, Marine and Chemical Research Institute were sought and placed before the Scientific Panel. The Scientific Panel, after detailed examination opined that since the present regulations of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 on plastic bottles specifies the safe overall migration limit of plastics in contact with food materials as 60 mg/kg, this would cover the migration of any micro plastics in water. Overall weight of micro plastic particles would be of the order of 0.01 mg/kg and well within the safe limit.

Sub-clause (b) of clause (4) of Sub-Regulation 4 of Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, have following provisions to check overall migration into the food;

> ' All packaging materials of plastic origin shall pass the prescribed overall migration limit of 60 mg/kg when tested as per Indian Standard, IS 9845 with no visible colour migration' .

डा. किरोड़ी लाल मीणा: माननीय सभापति जी, न्यूयार्क की स्टेट यूनिवर्सिटी में 9 देशों के बोतलबंद पानी की गुणवत्ता पर एक स्टडी की गई थी, जिसमें 90 परसेंट पानी के नमूनों में प्लास्टिक पाया गया। उन देशों में भारत भी शामिल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या micro plastic के कारण हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है और यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

डा. हर्ष वर्धन: महोदय. में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि जब न्यूयार्क स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी के बारे में हमारे पास जानकारी आई तो हमारे FSSAI का scientific panel, जो वॉटर तथा water beverages को deal करता है, ने तुरन्त सभी संबंधित संस्थानों –Indian Institute of Packaging, Indian Institute of Toxicology Research, Central Salt and Marine Chemical Research Institute के scientists के अतिरिक्त, अन्य संबंधित लोगों को बुलाकर इसकी जांच कराई। इस संदर्भ में मुझे बताना है कि plastic की जो migratory limit है, वह safe overall limit 60 मिलीग्राम per kg है लेकिन जो plastic के particles हैं, उनका साइज 0.01 microns है, इसलिए it has been found that they are absolutely within the safe limits. फिर भी अपनी research को हम और आगे, with all the stake-holders strengthen कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: सभापति जी, health hazards and पर्यावरण नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए, क्या भारत सरकार San Francisco की भांति, बोतल-बंद पानी को प्रतिबंधित करने का विचार रखती है?

डा. हर्ष वर्धन: जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, पिछले वर्ष World Environment Day पर, जब ' Beat Plastic Pollution' का theme सामने आया, भारत ने भी दुनिया के साथ मिलकर यह संकल्प किया कि हम वर्ष 2022 तक, प्रधान मंत्री जी के –' New India' –के सपने को साकार करने के लिए single use plastic को पूरी तरह से eliminate करेंगे। इसे ban करने से पहले, यह देखना आवश्यक है कि हम अपने आचरण और व्यवहार में इसे कितना ला सकते हैं। जब धीरे-धीरे उसका आन्दोलन विकसित होगा तो automatically मुझे लगता है कि ban जैसी स्थिति की तरफ हम अग्रसर होंगे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Chairman, Sir, the research conducted on pollution by plastic bottles at State University, New York, have reported the presence of micro plastics. The same report was placed before a scientific panel and various other Indian institutes, as the hon. Minister said. The reply says that the scientific panel has also opined. I would like to know whether the scientific panel has agreed with the report or declined it saying that it is wrong. Sir, (b) part of my question is this.

MR. CHAIRMAN: One supplementary, please.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, (b) part of the question.

MR. CHAIRMAN: No, no. No (b) part.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I think, obviously, the scientific panel has interpreted the results of the research team of New York. They have given their opinion that as per the rules and regulations and also the guidelines that have been framed till now by the FSSAI, the size of the plastic particles which are likely to migrate from the plastic bottles into the water or into food material, is well within the safe limit. They have further resolved that they will continue their research further in this particular direction with the help of all other stakeholders.

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, there are 14 crore households which don' t have access to drinking water. The Chennai water crisis shows that the promises that you had made have turned out to be hollow. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Tulsi*ji*, we are discussing plastic. You have gone to Chennai.

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, National Capital is expected to face similar crisis in 2020. The project which has been launched is expected to bring to fruition by 2024, but it has not been even formally launched.

MR. CHAIRMAN: This is not connected with the main question. Next, Shri Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA: Sir, though the Minister has given a very clear reply here and he has given the safety measures also but like these plastic particles in the water bottles, I want to know from the hon. Minister whether he is aware that there are some plastic rice also in the market which is imitating with the real rice. So, I want to know whether the Minister is aware of it, and if he is aware, what steps have been taken to check it.

DR. HARSH VARDHAN: I think the issue is well known to the FSSAI officials and they are keeping a close watch on the whole thing and doing whatever is required.

Promotion of tourism in Konkan area

*109. SHRI HUSAIN DALWAI: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government has taken any initiative for promoting tourism in Konkan area of Maharashtra, if so, the details thereof; the amount sanctioned and expenditure incurred since 2014 and if not, the reasons therefor;

(b) whether facilities have been provided by Government, so that, tourists could access these places of tourist interest, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) whether Government has considered constructing a crocodile park to provide habitat for their preservation in the backwaters of Konkan region, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI PRAHLAD SINGH PATEL): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Ministry of Tourism, under its different schemes has taken various initiatives for the Konkan region in Maharashtra as detailed below:–

The Ministry of Tourism under its Swadesh Darshan Scheme provides Central Financial Assistance to State Governments/Union Territory (UT) Administrations/Central Agencies for development of thematic tourist circuits in the country. Coastal circuit is one of the fifteen thematic circuits identified for development under the scheme. The projects under the scheme are identified for development in consultation with the State Governments/UT Administrations and are sanctioned subject to availability of funds, submission of suitable detailed project reports, adherence to scheme guidelines and utilization of funds released earlier. Details of the project sanctioned for the Sindhudurg Coastal Circuit, under the Swadesh Darshan Scheme are as follows:–

(₹ in crore)

Circuit Name/ Sanction Year	Project Name	Amount Sanctioned	Amount Released
Coastal Circuit (2015-16)	Development of the Sindhudurg Coastal Circuit (Shiroda Beach, Sagareshwar, Tarkarli, Vijaydurg (Beach and Creek), Devgad (Fort and Beach), Mitbhav, Tondavali, Mocehmad and Nivati Fort)	82.17	12.79